

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज

भोपाल, शनिवार 17 से 23 जनवरी 2026

भोपाल, मध्यप्रदेश से प्रकाशित

वर्ष- 13

अंक-75

पृष्ठ- 8

मूल्य- रु. 5 /-

मध्यप्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस-2026: भोपाल में आज शुरू, सीएम डॉ. मोहन यादव हुए शामिल

AI से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति, 500+ उद्योगपति और विशेषज्ञों की मौजूदगी; स्टार्टअप्स, जॉब्स और इनोवेशन पर फोकस

भोपाल : मध्य प्रदेश में आज 'मध्यप्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस-2026' का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह दो दिवसीय सम्मेलन भोपाल के एक प्रमुख होटल में आयोजित हो रहा है, जिसमें 500 से अधिक उद्योगपति, स्टार्टअप फाउंडर्स, AI विशेषज्ञ, नीति निर्माता और युवा उद्यमी भाग ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्घाटन सत्र में कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मध्य प्रदेश के विकास का नया इंजन बनेगा। हमारा लक्ष्य 2030 तक AI से जुड़े 1 लाख रोजगार सृजित करना और राज्य की अर्थव्यवस्था में 5% योगदान सुनिश्चित करना है। उन्होंने AI-आधारित कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने की घोषणा की।

कॉन्फ्रेंस में 8 सत्रों में AI के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हो रही है, जिसमें जेनरेटिव AI, मशीन लर्निंग, एथिकल AI और इंडस्ट्री 4.0 शामिल हैं। प्रमुख वक्ताओं में IIT, IIM के प्रोफेसर, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के विशेषज्ञ तथा स्टार्टअप लीडर्स शामिल हैं। एक सत्र में AI स्टार्टअप्स को फंडिंग और मेंटरिंग के अवसर दिए गए।



यह आयोजन मध्य प्रदेश को AI इनोवेशन हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ने AI पॉलिसी 2025 लॉन्च की है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रा पर फोकस है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कॉन्फ्रेंस 500 करोड़ से अधिक के निवेश और सैकड़ों स्टार्टअप्स को जन्म दे सकती है। जिसमें AI स्टार्टअप अवॉर्ड्स और निवेशकों के साथ मीटिंग्स होंगी। यह आयोजन 'विकसित मध्य प्रदेश' के विजन को नई दिशा देगा।

थोक महंगाई दिसंबर में बढ़कर 0.83% हुई: नवंबर में 0.32% की गिरावट के बाद उछाल

ईंधन और खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी से WPI में तेजी, RBI की मौद्रिक नीति पर असर संभव; अर्थव्यवस्था में मिश्रित संकेत

नई दिल्ली: भारत का थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर दिसंबर 2025 में बढ़कर 0.83% हो गई, जो नवंबर में -0.32% की गिरावट के बाद आई तेजी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, ईंधन और बिजली कीमतों में 4.5% की बढ़ोतरी तथा खाद्य वस्तुओं में मामूली उछाल मुख्य कारण रहे।

दिसंबर में ईंधन और बिजली समूह की महंगाई 4.52% रही, जो पिछले महीने -3.8% थी। खाद्य वस्तुओं का सूचकांक 1.2% बढ़ा, जबकि विनिर्मित उत्पादों की महंगाई 0.4% पर स्थिर रही। प्राथमिक वस्तुओं में भी 1.8% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल और घरेलू स्तर पर

डीजल-पेट्रोल की मांग से थोक महंगाई में यह बढ़ोतरी आई है।

हालांकि, यह दर अभी भी निचले स्तर पर है और खुदरा महंगाई (CPI) से काफी कम है, जो दिसंबर में 5.5% के आसपास रही। RBI के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि थोक महंगाई में यह उछाल अस्थायी हो सकता है, लेकिन यह मौद्रिक नीति की समीक्षा में विचार किया जाएगा।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि थोक महंगाई में यह बढ़ोतरी उत्पादन लागत बढ़ा सकती है, लेकिन अभी भी अर्थव्यवस्था में मांग मजबूत है। FY26 में औसत WPI महंगाई 2-3% रहने का अनुमान है। यह



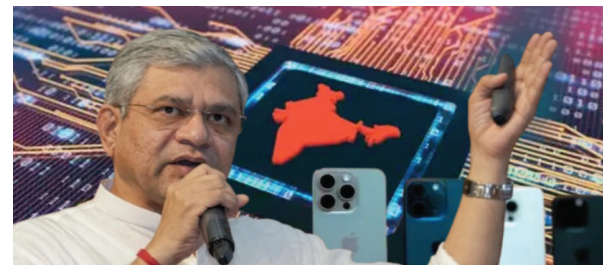
आंकड़ा वित्त वर्ष के अंतिम तिमाही में नीतिगत फैसलों को प्रभावित कर सकता है।

भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 2025 में 4 लाख करोड़ रुपये पार: आईटी मंत्री वैष्णव मोबाइल फोन और कंपोनेंट्स का निर्यात 70% बढ़ा, 2030 तक 10 लाख करोड़ का लक्ष्य; 'मेक इन इंडिया' और PLI स्कीम से मिली गति

मुंबई: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि वर्ष 2025 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 35% की वृद्धि दर्शाता है। मोबाइल फोन, लैपटॉप कंपोनेंट्स, चार्जर और सेमीकंडक्टर पार्ट्स के निर्यात में सबसे अधिक उछाल आया है। मंत्री वैष्णव ने कहा, 2025 में मोबाइल फोन निर्यात अकेले 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। यह 'मेक इन इंडिया' और PLI स्कीम की सफलता का प्रमाण है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश है, जहां एप्पल, सैमसंग और शाओमी जैसी कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन

कर रही हैं। 2025 में भारत से 30 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन निर्यात हुए, जिनमें से 60% अमेरिका और यूरोप गए। PLI स्कीम के तहत 76,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन से 20 से अधिक कंपनियों ने भारत में फैक्ट्रियां लगाईं। वैष्णव ने कहा, हमारा लक्ष्य 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 10 लाख करोड़ रुपये तक ले जाना है। सेमीकंडक्टर मिशन और गिफ्ट सिटी जैसे कदमों से भारत वैश्विक सप्लाय चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा आय में बड़ा योगदान देगी। FY25 में इलेक्ट्रॉनिक्स आयात 2 लाख

करोड़ रुपये था, लेकिन निर्यात में तेजी से ट्रेड डेफिसिट कम होगा। यह सफलता 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को मजबूत करती है।



SUVs Fuel Double-Digit Growth for Tata Motors Passenger Vehicles in 2026: CEO

Shailesh Chandra highlights strong order book, new launches and rising SUV preference driving 10–15% volume growth target for FY27

Mumbai: Tata Motors Passenger Vehicles is poised for strong double-digit growth in 2026, driven by surging demand for SUVs and an aggressive electric vehicle (EV) rollout, according to Managing Director and CEO Shailesh Chandra. Speaking at the company's investor day, Chandra highlighted that SUVs now account for over 70% of passenger vehicle sales, a trend expected to accelerate further.

2026 will be a pivotal year with multiple high-impact launches, including the Harrier EV and Sierra EV, alongside refreshed ICE models, Chandra said. The company plans to introduce five new EVs by FY30, with the Harrier EV leading in Q4 FY26. The Nexon and Punch, already market leaders, will receive significant updates to maintain their edge in the compact SUV segment.

Tata Motors recorded 22% growth in passenger vehicle deliveries in November 2025, with SUVs contributing the lion's share. Chandra attributed the momentum to rural recovery, higher disposable incomes, and growing preference for safety-focused, feature-rich vehicles. The company's EV portfolio-Nexon EV, Punch EV, Tiago EV, and Tigor EV continues to lead the market with over 65% share.

With a Rs 25,000 crore investment planned over five years, Tata Motors is strengthening battery localisation, charging infrastructure, and multi-powertrain flexibility. Analysts forecast 20-25% volume growth in FY26, supported by new launches and export expansion.

Shares of Tata Motors rose 2.8% to Rs 925 on BSE, reflecting market optimism. As India targets 30% EV penetration by 2030, Tata's SUV-led strategy positions it to dominate both conventional and electric segments.



The **asset** may be right
BUT
the **strategy** makes the **difference**

Want to run a check on your portfolio?
Just reply to this, and I'll guide you further

Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the documents carefully before investing.

Vision Invest Tech Private Limited
ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

(+91)7389912025 visionadvisorymkt@gmail.com



Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor



Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor



Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

Consumption 2.0: How Rising Incomes will Shape India's Equity Markets

India is entering a new phase of consumption growth, often described as Consumption 2.0. Unlike earlier phases driven mainly by basic needs, this new wave is powered by rising incomes, urbanisation, digital access, and changing lifestyles. As household earnings increase and aspirations grow, consumption is becoming one of the strongest drivers of corporate profits and stock market performance.

Over the past decade, India's per capita income has nearly doubled, crossing ₹1.9 lakh per year, according to government data. This rise in income has changed spending habits. Consumers are no longer focused only on essentials like food and clothing. Spending on automobiles, smartphones, branded goods, travel, healthcare, education, and housing is increasing steadily. This shift is clearly visible in company earnings and stock prices.

India has witnessed a similar phase before. Between 2003 and 2008, during a period of strong GDP growth and job creation, consumption stocks delivered exceptional returns. FMCG companies, auto manufacturers, banks, and retail-focused businesses outperformed the broader market as rising incomes translated into higher sales and profits. That period laid the foundation for many market leaders of today. Consumption 2.0 appears to be a broader and more sustained version of that cycle.

One major difference this time is scale and reach. Earlier, consumption growth was largely limited to metro cities. Today,

demand is rising from tier-2 and tier-3 cities, supported by better infrastructure, digital payments, UPI adoption, and e-commerce penetration. Affordable smartphones and internet access have brought millions of new consumers into the organised economy, benefiting listed companies.

The automobile sector is a clear example. Rising incomes and easy financing have increased demand for cars, two-wheelers, and premium vehicles. Companies like Maruti Suzuki, Tata Motors, and Mahindra & Mahindra have benefited from this trend. Similarly, consumer durable companies selling air conditioners, washing machines, and electronics have seen strong volume growth as aspirational buying increases.

The FMCG sector continues to remain a steady beneficiary. Large companies with strong distribution networks have reported better rural demand recovery as farm incomes and government support schemes improve purchasing power. Premiumisation where consumers upgrade from basic to branded products is also boosting margins and profitability.

Banking and financial services are another big winner of Consumption 2.0. As people spend more, they also borrow more for homes, vehicles, and personal needs. Retail loan growth has remained strong, supporting earnings for banks and NBFCs. During earlier consumption-led cycles, banking stocks consistently outperformed due to rising credit demand, and a similar trend is visible today.

What makes this phase stronger is policy

support and economic stability. Government focus on infrastructure, manufacturing, and employment generation is creating a virtuous cycle of income and spending. Formalisation of the economy through GST and digital payments has also improved transparency and corporate earnings visibility.

For the stock market, Consumption 2.0 means long-term earnings growth rather than short-term excitement. Companies linked to consumption tend to generate stable cash flows and benefit from compounding over time. Investors who stayed invested in consumption leaders during earlier cycles were rewarded handsomely.

In conclusion, rising incomes are reshaping how India spends, and this transformation is directly shaping equity markets. Consumption 2.0 is not just about higher spending it is about better-quality growth, wider participation, and long-term wealth creation. As India's middle class expands, consumption-driven businesses are likely to remain at the heart of India's equity story.

Dr. Irshad Ahmod
Khan
Sub-Editor



इंडियन आयल ने अबू धाबी में अपरंपरागत तेल भंडार की खोज की

ADNOC के साथ संयुक्त खोज, 1 अरब बैरल से अधिक संभावित भंडार; भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती, आयात निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम

नई दिल्ली: भारतीय तेल निगम (IOC) ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के साथ संयुक्त खोज अभियान में अबू धाबी में अपरंपरागत (अनकन्वेंशनल) तेल भंडार की खोज की है। यह खोज अबू धाबी के ऑनशोर क्षेत्र में शेल ऑयल और टाइट ऑयल के रूप में हुई है, जिसमें 1 अरब बैरल से अधिक तेल समकक्ष (BOE) का अनुमान है। IOC और ADNOC ने मंगलवार को संयुक्त बयान में इसकी पुष्टि की।

यह खोज दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग का नया अध्याय है। IOC के चेयरमैन शम्भु सिंह ने कहा, यह खोज भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और आयात निर्भरता को कम करने में मदद करेगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, जहां 85% तेल आयात होता है। अबू धाबी के साथ यह खोज भारत को सस्ते और स्थिर स्रोत प्रदान करेगी। प्रोजेक्ट में IOC ने 10% हिस्सेदारी ली है, जबकि ADNOC प्रमुख भागीदार है। खोज के बाद ड्रिलिंग और प्रोडक्शन टेस्टिंग शुरू होगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि व्यावसायिक उत्पादन 2028 तक शुरू हो सकता है। यह भारत का अबू धाबी में पहला अपरंपरागत तेल प्रोजेक्ट है।

यह सफलता 'ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को गति देगी। भारत 2030 तक तेल आयात में 10% कमी का लक्ष्य रखता है। ADNOC के साथ साझेदारी से भारत को तकनीकी विशेषज्ञता और निवेश भी मिलेगा। IOC के शेयर 1.8% चढ़े। यह खोज भारत-यूएई ऊर्जा संबंधों को और मजबूत करेगी।



Reliance Industries Allots Stake in RCPL to 13 Key Investors

Strategic Placement to Strengthen Retail and Consumer Play; Raises ₹2,500 Cr, Values RCPL at ₹1.2 Lakh Cr

Mumbai: Reliance Industries Limited (RIL) has allotted equity stake in its consumer retail arm, Reliance Consumer Products Limited (RCPL), to 13 marquee investors in a significant strategic placement. The transaction, valued at approximately ₹2,500 crore, was executed at a pre-money valuation of ₹1.2 lakh crore for RCPL, reflecting strong investor confidence in Reliance Retail's growth trajectory.

The investors include prominent global and domestic funds such as Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Qatar Investment Authority (QIA), Singapore's GIC, TPG, Silver Lake, KKR, and several family offices and high-net-worth individuals. The allotment was approved by the board and is part of Reliance's broader plan to unlock value in its consumer businesses while retaining majority control.

RCPL, the holding entity for Reliance Retail Ventures Ltd (RRVL), operates over 18,000 stores across grocery, fashion, electronics, and quick commerce through JioMart and other formats. The fresh capital will accelerate expansion in new categories, digital transformation, and supply chain enhancements. This partnership brings global expertise and long-term capital to fuel our consumer ecosystem, said Mukesh Ambani, Chairman, Reliance Industries.

The move follows Reliance's successful fundraising in Jio Platforms and other verticals. Analysts estimate RCPL's valuation could reach ₹2 lakh crore by 2028 as retail revenue crosses ₹5 lakh crore. The placement reduces promoter funding burden and strengthens the balance sheet.

Reliance Retail reported 25% revenue growth in FY25, with EBITDA margins improving. As India's consumer market targets \$4 trillion by 2030, RCPL's strategic partnerships position it to capture a larger share of organised retail and digital commerce.



Top queries related to Health Insurance

What are different types of health insurance?

What is Maternity, OPD, Ayurvedic/Homeopathy (AYUSH) cover?

What is a Network Hospital?

How many claims can I make?

Which is the best health insurance?

What is cashless treatment?

If your question is on this list

just reply and get all your answers, free of charge



Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

☎ (+91)7389912025 ✉ visionadvisorymkt@gmail.com



MIRACLE IS REAL

But, can you count on it all the time?



Buy term insurance and protect your family's financial future

Want to choose the right policy? Connect with me!



Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

☎ (+91)7389912025 ✉ visionadvisorymkt@gmail.com



Apparel Exporters Hanging by a Thread Amid New Tariff Threats

US 50% Duty Proposal on Indian Textiles Sparks Panic; Industry Fears 30-40% Export Drop, Urges Govt to Negotiate Early

New Delhi: India's ₹3.5 lakh crore apparel export sector is facing its biggest crisis in years as the United States prepares to impose up to 50% tariffs on textiles and garments from India. The proposed duties, part of President Donald Trump's aggressive trade policy targeting countries with large trade surpluses, have sent shockwaves through the industry, threatening millions of jobs and the survival of thousands of small and medium manufacturers.

The Apparel Export Promotion Council (AEPC) and the Clothing Manufacturers Association of India have warned that the tariffs could slash exports to the US-India's largest market accounting for 35% of shipments by 30-40% within the first year. This is an existential threat for many units, especially in Tirupur, Ludhiana, and Kolkata, said AEPC Chairman Narain Aggarwal. We are already losing competitiveness to Bangladesh and Vietnam, and these duties will make recovery impossible.

The US decision is linked to India's trade surplus of over \$30 billion

and its refusal to open up certain sectors. Apparel, which employs 4.5 crore workers (mostly women), contributes 7% to India's total exports and 2.3% to GDP. The sector has been struggling with high input costs, labour shortages, and global slowdown.

Industry leaders have urged the government to urgently engage with the US administration, offer concessions on select items, and expedite the India-US trade deal. We need immediate diplomatic intervention and support measures for exporters, said Sanjay K. Jain, Chairman of Textiles Committee.

With the threat looming, many exporters are exploring alternative markets like the EU, UK, and Middle East, but none can replace the US volume. The government has assured it is monitoring the situation closely.

As the clock ticks toward possible implementation in early 2026, the apparel industry is literally hanging by a thread, waiting for clarity and swift action to save its future.

L&T Bags Large Order from Torrent Energy Storage Solutions

Multi-Crore Contract for Battery Energy Storage System (BESS); Strengthens L&T's Position in India's Growing Energy Storage Market

Mumbai: Larsen & Toubro (L&T) has secured a 'large' order from Torrent Energy Storage Solutions Pvt Ltd for the engineering, procurement, and construction (EPC) of a Battery Energy Storage System (BESS). The company disclosed the development in a regulatory filing on Thursday, classifying the order value in the Rs 1,000-2,500 crore range under its 'large' category.

The project involves setting up a grid-scale BESS facility to support renewable energy integration, peak load management, and grid stability. L&T's Power Transmission & Distribution (PT&D) business vertical will execute the contract, leveraging its expertise in high-voltage systems and energy storage solutions. The project is expected to be completed within 24-30 months.



This order reinforces our leadership in India's energy transition ecosystem, said a L&T spokesperson. With renewables contributing over 40% of the energy mix, storage is critical for reliable power supply. The contract aligns with India's target of 500 GW non-fossil capacity by 2030 and the government's push for 50 GWh of battery storage by the same year.

Torrent Energy Storage Solutions, a subsidiary of Torrent Power, is expanding its renewable portfolio, including solar and wind projects across Gujarat and other states. The BESS will help balance intermittent renewable generation and reduce reliance on thermal backups. Analysts view the order as a strong positive for L&T, which has been aggressively expanding in renewables, green hydrogen, and energy storage. The company's order book now exceeds Rs 5 lakh crore, with renewables and transmission forming a growing share.

As India accelerates its clean energy transition, collaborations like this are expected to drive significant capex and job creation in the sector.

Alembic Pharmaceuticals Secures USFDA Tentative Approval for Generic Cancer Drug

Tentative Nod for Lenalidomide Capsules Strengthens Oncology Portfolio; Launch Expected Post-Patent Expiry, Boosting Revenue Potential

Vadodara : Alembic Pharmaceuticals Ltd has received tentative approval from the US Food and Drug Administration (USFDA) for its generic version of Lenalidomide capsules, a key cancer treatment drug. The approval, granted for multiple strengths (2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, and 25 mg), positions Alembic to launch the product in the US market upon expiry of the originator patent.

Lenalidomide, marketed by Bristol Myers Squibb under the brand Revlimid, is widely used for treating multiple myeloma, myelodysplastic syndromes, and mantle cell lymphoma. The drug generated over \$12 billion in global sales for the innovator before generics entered the market. Alembic's tentative approval allows the company to prepare for commercial launch, pending final approval and settlement of any ongoing patent litigation.

This tentative approval further strengthens our oncology portfolio and reinforces our commitment to providing affordable medicines to patients worldwide, said a company spokesperson. Alembic already has a robust generics pipeline in the US, with over 180 ANDAs approved and more than 50



tentative approvals pending. Analysts expect the Lenalidomide generic to contribute meaningfully to revenue once launched, given the high demand in the US oncology market. The tentative nod comes amid Alembic's ongoing focus on complex generics and specialty products, with oncology forming a key growth driver.

With the US generics market remaining a major revenue source, this approval enhances Alembic's competitive positioning and long-term growth prospects in high-value therapeutic areas.

SIF Inflows Surge to Rs 1,933 Crore in December, Momentum Strong in Early 2026: AMFI

Specialised Investment Funds See Sharp Uptick; Equity and Thematic SIFs Lead as Investors Seek Diversified High-Growth Exposure

Mumbai: Specialised Investment Funds (SIFs) witnessed a sharp acceleration in inflows during December 2025, attracting Rs 1,933 crore the highest monthly figure since their launch according to data released by the Association of Mutual Funds in India (AMFI). The robust momentum has continued into the early weeks of 2026, reflecting sustained investor interest in these high-conviction, thematic, and sector-focused products.

SIFs, introduced in 2024 as a bridge between mutual funds and PMS/AIFs, allow fund managers to take concentrated bets in select themes, sectors, or strategies with minimum investment of Rs 5 lakh. December's inflows were led by equity-oriented and thematic SIFs, which accounted for 68% of the total, driven by optimism in mid-cap, small-cap, and emerging themes such as infrastructure, defence, and green energy.



AMFI CEO Venkateshwaran Iyer said, SIFs are gaining traction among investors seeking higher alpha through specialised strategies. The category has grown from Rs 2,500 crore AUM in early 2025 to over Rs 12,000 crore now, with inflows remaining strong in the new year. The December figure represents a 45% sequential increase and reflects growing retail and HNI participation alongside institutional interest.

Industry experts attribute the surge to falling fixed-income returns, equity market resilience, and increased awareness through digital platforms. With 28 SIFs now live across 15 AMCs, the category is expected to cross Rs 25,000 crore AUM by March 2026.

As India's mutual fund industry races toward Rs 70 lakh crore AUM, SIFs are emerging as a key growth engine, offering investors sophisticated yet regulated access to high-conviction ideas in a maturing market.

UPI यूजर बेस 1 अरब से अधिक हो सकता है: RBI डिप्टी गवर्नर की भविष्यवाणी

डिजिटल पेमेंट्स में भारत की तेजी, 2026 तक 50% ग्रोथ संभव; ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाने से होगा बड़ा उछाल

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर टी. रवि शंकर ने कहा है कि यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के यूजर बेस को 1 अरब से अधिक तक पहुंचने की क्षमता है। वर्तमान में UPI के 50 करोड़ से अधिक एक्टिव यूजर्स हैं, और यह संख्या अगले कुछ वर्षों में दोगुनी से भी अधिक हो सकती है। डिप्टी गवर्नर ने एक सेमिनार में कहा, UPI भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुका है। ग्रामीण और छोटे शहरों में इसका तेज प्रसार हो रहा है।

रबी शंकर ने बताया कि 2025 में UPI ट्रांजेक्शन की संख्या 15 अरब से अधिक हो गई, जो वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा है। दिसंबर 2025 में अकेले 18 अरब से अधिक ट्रांजेक्शन हुए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने से UPI का विस्तार

और तेज होगा। RBI ने UPI को और सुलभ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे UPI लाइट और क्रेडिट-ऑन-UPI विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में UPI ट्रांजेक्शन 20 अरब से अधिक हो सकते हैं। यह भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति का प्रमाण है, जहां कैशलेस ट्रांजेक्शन 70% से अधिक हो चुके हैं। RBI का लक्ष्य 2030 तक 100% डिजिटल पेमेंट्स है। डिप्टी गवर्नर ने कहा कि UPI ने छोटे व्यापारियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है।

यह भविष्यवाणी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। UPI अब 50 से अधिक देशों में उपलब्ध है। यह विकास 'डिजिटल इंडिया' के विजन को मजबूत करेगा।



नेट डायरेक्ट टैक्स संग्रह 11 जनवरी तक 8.8% बढ़ा: टैक्सपेयर्स का भरोसा कायम

11.5 लाख करोड़ रुपये का संग्रह, कॉर्पोरेट टैक्स में तेजी; बजट 2026 से पहले राजस्व लक्ष्य की ओर मजबूत कदम

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2025-26 में नेट डायरेक्ट टैक्स संग्रह 11 जनवरी तक 11.5 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.8% अधिक है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, यह वृद्धि कॉर्पोरेट टैक्स (10.2%) और पर्सनल इनकम टैक्स (7.5%) दोनों में हुई है। इस दौरान ग्रास संग्रह 13.8 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि रिफंड 2.3 लाख करोड़ रुपये दिए गए।

कॉर्पोरेट टैक्स में तेजी का कारण कंपनियों की मजबूत कमाई और बेहतर अनुपालन है। पर्सनल टैक्स में भी सैलरीड क्लास और प्रोफेशनल्स की बढ़ती संख्या ने योगदान दिया। TDS और एडवांस टैक्स संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई। वित्त वर्ष की पहली छमाही

में संग्रह लक्ष्य का 75% से अधिक हासिल हो चुका है, जो पूरे साल के 22 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य की ओर मजबूत संकेत देता है।

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, टैक्स बेस का विस्तार, बेहतर अनुपालन और डिजिटल ट्रैकिंग से संग्रह में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह आंकड़ा अर्थव्यवस्था में स्थिरता और मध्यम वर्ग की बढ़ती आय को दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बजट 2026 में टैक्स स्लैब में राहत और कॉर्पोरेट टैक्स में स्थिरता से संग्रह और बढ़ सकता है।

यह वृद्धि भारत की आर्थिक रिकवरी और फिस्कल डिसिप्लिन का प्रमाण है। सरकार का फोकस टैक्स बेस बढ़ाने और रिफंड प्रक्रिया को तेज करने पर है।



MPBIL/2013/48052
INVESTMENT AVENUES®
(इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज)
(A Publication of Vision Invest Tech Pvt. Ltd.)

INVESTMENT AVENUES CALL FOR ARTICLES

Share Your Knowledge with
INVESTMENT AVENUES

We invite individual, professionals, and
entrepreneurs to contribute their
expertise and experiences.

- STOCK MARKET
- MUTUAL FUNDS
- REAL ESTATE
- STARTUPS & ENTREPRENEURSHIP

Guidelines:

1. Article must be original
2. Submit in MS Word format
3. Length should not exceed 500 words

editor@investmentavenues.in

write with us, inspire others, and make
your voice heard in the world of investments!

INVESTMENT AVENUES®

Looking To Invest In Real Properties &
Valued Businesses In Bhopal

Discover genuine real estate and well-assessed business
opportunities — safe-to-invest and growth-oriented.

Secure Deals. Smart Investments.



EMAIL: INVESTMENTAVENUES90@GMAIL.COM
CONTACT: +91 73899 26586

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj

Technical Head

anil.stockcare@gmail.com

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

- As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
- If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1

- If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
- Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
- If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
- If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	losing Rat	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	25694	26326	26111	25903	25688	25480	25265	25057
BANK NIFTY	60095	61837	60998	60546	59707	59255	58416	57964
SENSEX	83570	85590	84903	84236	83549	82882	82195	81528
FINNIFTY	27523	28207	27964	27744	27501	27281	27038	26818
MIDCAP	13698	14216	14030	13864	13678	13512	13326	13160
ACC	1756	1860	1811	1784	1735	1708	1659	1632
AXISBANK	1296	1374	1341	1319	1286	1264	1231	1209
ABCAPITAL	361	387	376	368	357	349	338	330
BHARTIARTL	2018	2108	2079	2048	2019	1988	1959	1928
BHEL	266	287	280	273	266	259	252	245
BIOCON	377	405	395	386	376	367	357	348
CDSL	1433	1514	1482	1458	1426	1402	1370	1346
DATAPATTERN	2538	2766	2714	2626	2574	2486	2434	2346
ESCORTS	3676	3941	3879	3778	3716	3615	3553	3452
EICHERMOTOR	7300	7732	7622	7461	7351	7190	7080	6919
FEDERAL BANK	270	312	293	281	262	250	231	219
GRINFRAPROJECT	918	1002	982	950	930	898	878	846
HDFCBANK	930	973	961	945	933	917	905	889
HCLTECH	1698	1799	1750	1724	1675	1649	1600	1574
HINDUNILVR	2362	2490	2456	2409	2375	2328	2294	2247
HAL	4433	4717	4635	4534	4452	4351	4269	4168
HYUNDAI	2342	2501	2425	2384	2308	2267	2191	2150
IOC	161	171	166	164	159	157	152	150
ICICIBANK	1414	1492	1467	1441	1416	1390	1365	1339
INFY	1689	1836	1764	1727	1655	1618	1546	1509
ITC	329	349	344	337	332	325	320	313
KOTAKBNK	419	437	432	426	421	415	410	404
LICHOUSING	532	572	557	544	529	516	501	488
LT	3857	4169	4098	3978	3907	3787	3716	3596
LUPIN	2174	2291	2254	2214	2177	2137	2100	2060
MARUTI	15877	17432	17078	16478	16124	15524	15170	14570
M&M	3660	3858	3794	3727	3663	3596	3532	3465
MGL	1063	1107	1092	1077	1062	1047	1032	1017
MAZGAONDOC	2447	2649	2598	2522	2471	2395	2344	2268
PFC	374	408	393	384	369	360	345	336
RECLTD	372	399	388	380	369	361	350	342
RELIANCE	1461	1526	1506	1483	1463	1440	1420	1397
SBIN	1041	1111	1079	1060	1028	1009	977	958
SUNPHARMA	1671	1809	1776	1724	1691	1639	1606	1554
SHRIRAMFINANCE	997	1085	1054	1025	994	965	934	905
TITAN	4194	4404	4343	4268	4207	4132	4071	3996
TCS	3208	3367	3321	3265	3219	3163	3117	3061
TATAMOTORS	354	375	367	361	353	347	339	333
UPL	794	840	819	806	785	772	751	738
VALIENT	247	274	268	258	252	242	236	226
WIPRO	267	281	276	271	266	261	256	251

केपी ग्रुप गुजरात में 4,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा: बड़ा औद्योगिक विस्तार

रिन्यूएबल एनर्जी और मैनुफैक्चरिंग में फोकस, 5,000 नौकरियां सृजित होंगी; राज्य को हरित ऊर्जा हब बनाने में योगदान

अहमदाबाद: केपी ग्रुप ने गुजरात में 4,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का ऐलान किया है। यह निवेश रिन्यूएबल एनर्जी, मैनुफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में किया जाएगा। कंपनी ने 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट' के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में MoU पर हस्ताक्षर किए।

केपी ग्रुप के चेयरमैन फरूक पटेल ने कहा, गुजरात में हमारी मौजूदा उपस्थिति को देखते हुए हम और विस्तार कर रहे हैं। यह निवेश 5,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगा। निवेश का बड़ा हिस्सा सौर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में जाएगा, जिसमें 1 GW से अधिक रिन्यूएबल क्षमता जोड़ी जाएगी। इसके अलावा, कंपनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भी निवेश करेगी।

गुजरात सरकार ने कंपनी को लैंड और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। यह निवेश राज्य के 100 GW रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य (2030) को मजबूत करेगा। केपी ग्रुप पहले से गुजरात में सौर मॉड्यूल्स और पावर ट्रांसमिशन में सक्रिय है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम गुजरात को हरित ऊर्जा और मैनुफैक्चरिंग हब बनाने में मदद करेगा। राज्य में हाल के वर्षों में 10 लाख करोड़ से अधिक निवेश के प्रस्ताव आए हैं। केपी ग्रुप का यह निवेश 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को समर्थन देगा। कंपनी के शेयर बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया आई। यह घोषणा गुजरात की आर्थिक प्रगति का नया अध्याय लिखेगी।



Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.